+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(08 November 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- मोदी 3.0 और ट्रंप 2.0; दोनों भारत-अमेरिका संबंधों को कैसे आकार देंगे?
- शिक्षा वह सीक्रेट है, जिसने चीन को विकास के मामले में भारत से आगे निकलने में मदद की

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

मोदी 3.0 और ट्रंप 2.0; दोनों भारत-अमेरिका संबंधों को कैसे आकार देंगे?

परिचय:

- डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापस लौटने के साथ ही, इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि उनका दूसरा कार्यकाल अमेरिकी विदेश नीति और खास तौर पर भारत-अमेरिका संबंधों को कैसे आकार देगा। ट्रंप की विदेश नीति ने हमेशा "अमेरिका फर्स्ट" पर जोर दिया है, जो यह दर्शाता है कि उनके अगले कार्यकाल में और अधिक स्पष्ट पृथकतावाद की पहचान हो सकती है।
- हालांकि, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके मधुर संबंध जो एक अद्‌वितीय कूटनीतिक आधार का वादा करते हैं। दोनों नेताओं के बीच यह बंधन दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- अगर ट्रंप 2.0 विश्व में चल रहे दो विनाशकारी युद्‌धों को समाप्त कर पाते हैं, तो भारत को भी इसका बहुत फायदा हो सकता है।

राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच महत्वपूर्ण मित्रता:

- राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच की दोस्ती ने भारत-अमेरिका संबंधों में एक मिसाल कायम की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने व्यापार समर्थक रुख और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करके राष्ट्रपति ट्रंप में एक समान विचारधारा वाला साथी पाया है।
- दोनों नेता व्यापार नवाचार, विनियमन और आर्थिक विकास के उद्देश्य से नीतियों का समर्थन करते हैं। उनके नेतृत्व में, भारत और अमेरिका संभावित रूप से वैश्विक आर्थिक मंच पर महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
- दोनों राष्ट्र समान हितों से प्रेरित हैं: भारत का लक्ष्य दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, जबकि अमेरिका चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए विश्वसनीय सहयोगियों की तलाश कर रहा है। उनकी घनिष्ठ मित्रता निरंतरता का संकेत देती है, जो साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है।
- ट्रंप-मोदी गठबंधन न केवल आर्थिक संबंधों को गहरा कर सकता है, बल्कि आतंकवाद और इंडो-पैसिफिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर रणनीतिक संरेखण भी प्रदान कर सकता है।

- भारत के रणनीतिक स्थान और बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, दोनों नेता एक-दूसरे की ताकत को बढ़ा सकते हैं और अन्य गठबंधनों में एक लहर प्रभाव पैदा कर सकते हैं।

अमेरिका में बदलती जनसांख्यिकी और भारतीय-अमेरिकी वोट:

- प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति ट्रंप के रिश्ते अमेरिका के भीतर राजनीतिक परिदृश्य को भी आकार दे सकते हैं। पारंपरिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रति वफादार भारतीय-अमेरिकियों के बीच हाल के वर्षों में रूढ़िवादी मूल्यों की ओर बदलाव आया है।
- बिडेन प्रशासन की विनियामक नीतियों की आलोचना इस समुदाय के साथ प्रतिध्वनित हुई है, जो व्यापार-अनुकूल नीतियों, परिवार-उन्मुख रूढ़िवाद और कम करों को महत्व देता है।
- डोनाल्ड ट्रंप की "अमेरिका फ़र्स्ट" बयानबाजी, जिसे अक्सर पृथकतावाद के रूप में देखा जाता है, ने भारतीय-अमेरिकी समुदाय के उन वर्गों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है जो रिपब्लिकन पार्टी को अपने मूल्यों और आर्थिक लक्ष्यों के साथ अधिक संरेखित मानते हैं।

- यह बदलता जनसांख्यिकीय परिदृश्य भविष्य की राजनीतिक गणना को बदल सकता है। भारतीय-अमेरिकी अमेरिका में सबसे धनी और सबसे शिक्षित अप्रवासी समूहों में से हैं। रूढ़िवाद की ओर उनके बदलाव से इस समुदाय के भीतर रिपब्लिकन का प्रभाव बढ़ सकता है, खासकर जब वे ऐसी नीतियों की तलाश करते हैं जो व्यापार विकास, कम विनियमन और कम करों को बढ़ावा देती हैं।

आर्थिक संबंधों में पारस्परिकता और तनाव:

- दोनों देशों के बीच व्यापार एक नाजुक मुद्दा रहने वाला है, खासकर राष्ट्रपति ट्रम्प के "पारस्परिक करों" पर रुख के साथ। अपने 2016 के राष्ट्रपति पद के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप ने अक्सर उन देशों की आलोचना की, जिन्होंने अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाए थे, और भारत इसका अपवाद नहीं था।
- भारत के लिए, बढ़े हुए टैरिफ आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल जैसे उद्योगों को चुनौती दे सकते हैं जो अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं।
- हालांकि, अगर ट्रंप चीन से अलग होने पर जोर देते हैं तो इससे भारत को फायदा हो सकता है, संभावित रूप से इसके विनिर्माण क्षेत्र में अधिक अमेरिकी निवेश आकर्षित हो सकता है।

- यह अलगाव भारत को, अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की इच्छुक अमेरिकी कंपनियों के लिए, एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

आव्रजन नीति संबंधों में एक विवादास्पद मुद्दा:

- आव्रजन नीति भारत-अमेरिका संबंधों में एक विवादास्पद मुद्दा बनी हुई है, खासकर भारतीय पेशेवरों के लिए। राष्ट्रपति ट्रंप के पिछले प्रशासन ने एच-1बी वीजा के लिए सख्त आवश्यकताएं पेश कीं, जो भारतीय तकनीकी पेशेवरों और व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
- इन प्रतिबंधों ने भारतीय नागरिकों और व्यापक तकनीकी उद्योग के बीच चिंताएँ बढ़ा दीं, जो कुशल विदेशी प्रतिभाओं पर निर्भर करता है। इन नीतियों को फिर से लागू करने से भारत की प्रतिभा पाइपलाइन प्रभावित हो सकती है और अमेरिका में भारतीय पेशेवरों पर असर पड़ सकता है।
- हालांकि, अगर दोनों नेता आव्रजन पर समझौता करने में कामयाब हो जाते हैं, तो यह भारत-अमेरिका सहयोग में एक नया अध्याय जोड़ सकता है।

इंडो-पैसिफिक में रक्षा और सुरक्षा:

- भारत-अमेरिका रक्षा संबंध हाल के वर्षों में काफी बढ़ गए हैं, खासकर इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (iCET) और प्रमुख रक्षा सौदों जैसे कदमों के साथ। राष्ट्रपति ट्रंप का दूसरा कार्यकाल इन क्षेत्रों के लिए अधिक लेन-देन वाला दृष्टिकोण ला सकता है, जिससे संभावित रूप से रक्षा सौदे भारत की अपनी प्रतिबद्धताओं पर सशर्त हो सकते हैं।
- राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान चीन के प्रति संतुलन के रूप में क्वाड को बढ़ावा दिया गया था। ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में, क्वाड पहलों पर और अधिक जोर देने से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका मजबूत हो सकती है। सैन्य सहयोग बढ़ाकर, अमेरिका और भारत संयुक्त रूप से चीन की मुखर नीतियों को संबोधित कर सकते हैं, जो एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

आतंकवाद का मुकाबला: एक साझा लक्ष्य

- आतंकवाद का मुकाबला राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के लिए साझा हित का क्षेत्र रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान, उनका "शक्ति के माध्यम से

शांति" सिद्धांत भारत की सुरक्षा प्राथमिकताओं, विशेष रूप से पाकिस्तान के संबंध में, के साथ अच्छी तरह से संरेखित था।

- ट्रम्प-मोदी साझेदारी आतंकवादी खतरों का मुकाबला करने और चरमपंथ को संबोधित करने के लिए संयुक्त प्रयासों को मजबूत कर सकती है।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लंबे समय से आतंकवाद पर एक सख्त रुख की वकालत की है, और विदेश नीति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का बेबाक दृष्टिकोण आतंकवादी नेटवर्क का मुकाबला करने में समन्वित प्रयासों को जन्म दे सकता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को लाभ होगा।
- राष्ट्रपति ट्रम्प के तहत एक मजबूत यूएस-भारत आतंकवाद विरोधी साझेदारी आतंकवादी समूहों को पनाह देने वाले देशों पर कूटनीतिक दबाव डाल सकती है, जिससे भारत का सुरक्षा वातावरण बेहतर हो सकता है।

संतुलित और मजबूत संरेखण की ओर:

- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ट्रंप की पृथकतावादी विदेश नीति और प्रधानमंत्री मोदी का व्यापार समर्थक रुख भारत-अमेरिका संबंधों के लिए एक जटिल पृष्ठभूमि प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय समझौतों में अमेरिका की भागीदारी को कम करने पर ट्रंप का ध्यान मोदी के वैश्विक रूप से जुड़े भारत के दृष्टिकोण के विपरीत है।

- फिर भी, दोनों नेता आर्थिक विकास और राष्ट्रीय संप्रभुता को महत्व देते हैं, और वे साझा चिंताओं को दूर करने के लिए इन साझा मूल्यों का लाभ उठा सकते हैं।
- आने वाले वर्षों में, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप संतुलन खोजने : प्रत्येक राष्ट्र की नीतिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- उदाहरण के लिए, यदि राष्ट्रपति ट्रंप अधिक न्यायसंगत व्यापार सौदों के लिए दबाव डालते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार घरेलू आर्थिक नीतियों से समझौता किए बिना भारतीय निर्यात के लिए नए रास्ते खोलने वाली शर्तों पर बातचीत करने की कोशिश कर सकती है। इसी तरह, वैश्विक पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं में मोदी का नेतृत्व ट्रम्प को उनके सिद्धांत के साथ संघर्ष किए बिना नवीकरणीय ऊर्जा जैसे मुद्दों पर सहयोग करने का मार्ग प्रदान कर सकता है।
- उल्लेखनीय है कि व्यापार, रक्षा और साझा क्षेत्रीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप एक ऐसी साझेदारी बना सकते हैं जो न केवल भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करेगी बल्कि लोकतंत्रों के बीच गठबंधन के लिए एक नई मिसाल भी स्थापित करेगी।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

शिक्षा वह सीक्रेट है, जिसने चीन को विकास के मामले में भारत से आगे निकलने में मदद की:

परिचय:

- दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों ने लगभग एक ही समय में, 1990 के दशक की शुरुआत में दुनिया के लिए खुलना शुरू किया था। लेकिन जहां दोनों ने तेजी से विकास किया और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, वहीं अब चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा है, जब उनकी मुद्राओं को उनकी वास्तविक क्रय शक्ति के हिसाब से समायोजित किया जाता है।

दोनों देशों के प्रदर्शन के अंतर के पीछे कारण क्या है?

- उल्लेखनीय है कि 1990 के दशक की शुरुआत से चीन और भारत ने वैश्वीकरण के लिए बिल्कुल अलग-अलग रास्ते अपनाए। चीन ने जहां खिलौनों और इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरुआत करके दुनिया की फैक्ट्री बनने की ठानी और फिर इलेक्ट्रिक कारों और

सेमीकंडक्टर की तरफ़ बढ़ गया। वहीं भारत ने कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर जैसी सेवाओं पर ज़ोर दिया।

- उनकी जनसंख्या संरचना भी अलग-अलग थी। एक-बच्चे की नीति ने युवाओं की एक बड़ी संख्या को जन्म दिया और चीन को बूढ़ा होने से पहले ही अमीर देश के दरवाजे पर ला खड़ा किया है। जबकि भारत की जनसांख्यिकीय नियति अब सामने आ रही है, हालांकि अधिशेष कृषि श्रम को अवशोषित करने के लिए नौकरियां नहीं हैं।
- और फिर राजनीतिक संस्थाओं में भी अंतर है। चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है, जबकि भारत में बहुदलीय, चुनावी लोकतंत्र है।

दोनों द्वारा आधुनिक शिक्षा को अपनाने के लंबे इतिहास में एक तीव्र बदलाव है?

- यह पारंपरिक विचारधारा है। लेकिन क्या होगा अगर सतह के नीचे एक और अधिक मौलिक शक्ति काम कर रही हो, जो दोनों देशों द्वारा आधुनिक शिक्षा को अपनाने के लंबे इतिहास में एक तीव्र अंतर को दर्शाती हो? यही नितिन कुमार भारती और ली यांग द्वारा लिखे गए नए शोधपत्र, "21वीं सदी में चीन और भारत का निर्माण" की थीसिस है।

- पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के विद्वानों ने 1900 से लेकर अब तक की आधिकारिक रिपोर्टों और सालाना पुस्तकों का गहन अध्ययन किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दोनों देशों में किसने क्या पढ़ा, कितने समय तक और उन्हें क्या पढ़ाया गया। पिछले 100 वर्षों में चीन और भारत द्वारा निर्धारित अलग-अलग पाठ्यक्रमों ने मानव पूंजी और उत्पादकता के लिए आश्चर्यजनक परिणाम दिए हैं।

इस शोध पत्र का प्रमुख निष्कर्ष:

- पश्चिमी शिक्षा के संपर्क में 50 साल की बढ़त के कारण, भारत में 20वीं सदी की शुरुआत में छात्रों की संख्या चीन से आठ गुना ज्यादा थी। 1905 में शाही परीक्षा प्रणाली के उन्मूलन और कन्फ्यूशियसवाद को अलविदा कहने के बाद ही चीन ने इस मामले में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। 1930 के दशक तक, इसने भारत के कुल नामांकन के बराबरी हासिल कर ली थी।
- 1950 के दशक में, नवगठित पीपुल्स रिपब्लिक ने विस्तार की स्थिर गति बनाए रखी, यहाँ तक कि सांस्कृतिक क्रांति (1966-1976) को माध्यमिक स्कूली शिक्षा के रास्ते में आने नहीं दिया।

- जबकि 1980 के दशक की शुरुआत में, भारत का कॉलेज नामांकन अनुपात चीन की तुलना में पाँच गुना अधिक था। हालांकि, 2020 तक कहानी बदल गई थी: चीन भारत की तुलना में अपने विश्वविद्यालय-आयु वर्ग के एक बड़े हिस्से को तृतीयक संस्थानों में भेज रहा था।

दोनों देशों के मध्य अंतर की ऐतिहासिक जड़े:

- अलग-अलग प्रक्षेप पथों की जड़ें इतिहास में हैं। चीन के 19वीं सदी के उत्तरार्ध के किंग राजवंश के शासक सैन्य-संबंधी उत्पादन को संभालने के लिए व्यावसायिक कौशल वाले जनशक्ति चाहते थे।
- इसके विपरीत, भारत के ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वामियों की विनिर्माण आधार बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उन्होंने शिक्षा प्रणाली में क्लर्क और जूनियर प्रशासकों को तैयार करने के लिए पूर्वाग्रह का बीजारोपण किया।
- समाज के केवल अधिक संपन्न वर्गों के पास ही सरकारी नौकरियों और उन्हें पाने के लिए आवश्यक शिक्षा तक पहुँच थी।
- 1947 में स्वतंत्रता के बाद, भारत ने उच्च शिक्षा संस्थानों पर दोगुना निवेश किया, बुनियादी शिक्षा और गणित कौशल की कीमत पर कुलीन कॉलेजों में निवेश किया गया।

भारत में उच्च शिक्षा पर जोर देने का निर्णय टॉप-डाउन विकल्प:

- भारती-यांग अध्ययन के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा पर जोर देने का निर्णय टॉप-डाउन विकल्प था, जहां 1960 के दशक में पैदा हुए आधे व्यक्ति निरक्षर रह गए, जबकि चीन में यह आंकड़ा 10 प्रतिशत था।
- अधिकांश स्कूली आयु वर्ग के भारतीय बच्चे जल्दी ही पढ़ाई छोड़ देते हैं (यदि उन्होंने पढ़ाई शुरू भी की हो), या तो इसलिए क्योंकि उनके गांवों में पढ़ाने के लिए कोई नहीं आया, या इसलिए क्योंकि परिवार के श्रम पूल को बढ़ाने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता थी।
- बॉटम-अप की रणनीति में बड़ी संख्या में युवा विद्यार्थियों को पांच साल की शिक्षा देना, फिर उनमें से बढ़ते हुए बड़े उपसमूह को कुल 12 साल की शिक्षा के लिए हाई स्कूल में जाने में सक्षम बनाना शामिल है - 16 साल की शिक्षा के लिए रास्ते खोलने से पहले। चीन ने यही चुना।

भारत में स्नातक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की अधिकता:

- अध्ययन का एक और भी ज़्यादा चौंकाने वाला निष्कर्ष कॉलेज की पढ़ाई के बारे में है। ऐतिहासिक रूप से, भारत में स्नातक की डिग्री स्तर पर सामाजिक विज्ञान

स्नातकों की अधिकता रही है। हालांकि, चीन में, 1930 के दशक की शुरुआत में ही मानविकी, कानून और व्यवसाय का अधिक प्रतिनिधित्व कम होने लगा, क्योंकि ज्यादातर स्नातक शिक्षक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर और कृषि विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षित होने लगे।

- इसका विकास पर असर पड़ सकता है। जैसा कि केविन मर्फी, आंद्रेई श्लेफ़र और रॉबर्ट विश्नी द्वारा 1991 में लिखे गए एक पेपर से पता चलता है, जो देश तेजी से विस्तार करना चाहता है, उसे वकीलों से ज़्यादा इंजीनियरों की जरूरत होती है।
- उल्लेखनीय है कि आम धारणा यह है कि भारत "इंजीनियरों की भूमि" है। यह सच है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प और अल्फाबेट इंक के सीईओ समेत कई टेक-इंडस्ट्री के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत में पैदा हुए और यहीं पढ़े-लिखे हैं। लेकिन चीन के हाई-स्पीड ट्रेन नेटवर्क का विशाल विस्तार - या इसके ईवी का परिष्कार - दिखाता है कि भारती और यांग ने चीन की प्रतिस्पर्धात्मकता के अक्सर अनदेखा किए जाने वाले स्रोत पर ध्यान केंद्रित किया है।
- लेखकों का कहना है, "चीन में इंजीनियरिंग और व्यावसायिक स्नातकों की उच्च हिस्सेदारी, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की उच्च हिस्सेदारी के साथ मिलकर, विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक आसानी से अनुकूल है"।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

शोध अध्ययन के निष्कर्षों का महत्व:

- 1992 में डेंग शियाओपिंग के दक्षिणी चीन के दौरे ने कम्युनिस्ट पार्टी की प्रधानता को बनाए रखते हुए पश्चिम से पूंजी के साथ जुड़ने की चीन की इच्छा का संकेत दिया। कुछ ही महीने पहले, तत्कालीन नए भारतीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने भी दशकों के सोवियत-प्रेरित समाजवाद और अलगाववाद से निर्णायक रूप से नाता तोड़ लिया था। उन्होंने कहा कि भारत एक प्रमुख आर्थिक अभिनेता बनने जा रहा है।
- हालांकि, इतिहास के अवशेषों को अक्सर दूर करना मुश्किल होता है। अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा में जो टॉप-डाउन, अभिजात्य पूर्वाग्रह डाला था, वह आज भी कायम है।